फोनः-4103333, 2362400 फैक्सः-0141-2373513 वर्षः 77 संख्याः 60 प्रभात जयपुर, बुधवार 30 सितम्बर, 2026 डाक पं.सं. जयपुर सिटी/001/2021-23 पृष्ठ 8 मूल्य 2.75 रु.

ARBiT

जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

epaper.rashtradoot.com

राष्ट्रदूत

Metro

Rashtradoot

Beware of Luxury

The children are not the problem here. They show us what happens when adults stop watching. This house is not falling apart later. It is falling apart now

The Art of Designing Before the Loom

The Underground Elephants of Mount Elgon

राहुल गांधी ने सीडब्ल्युसी में पुरजोर शब्दों में कहा, ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए हम अंत तक लड़ेंगे

'मोदी स्वयं ज्ञानेश को हटाएंगे, जैसे धर्मेन्द्र प्रधान को हटाना पड़ा था'

- इस प्रसंग पर चर्चा करते हुए राहुल गांधी ने एक किस्सा भी सुनाया।
- किस्से के अनुसार, विपक्ष के नेता बनने के बाद उन्होंने प्र.मंत्री व गृह मंत्री से कहा कि मैं कुछ नियुक्तियों का विरोध कर रहा हूँ, विपक्ष के नेता के रूप में, चयन समिति का सदस्य होने के नाते से, तो आप उन व्यक्तियों को ऊंचे पदों पर लगातार नियुक्त कैसे किए जा रहे हैं।
- इस पर मोदी जी ने कहा, ठीक उसी तरह से, जैसे इंदिरा गांधी करती थीं।
- तब, राहुल गांधी के अनुसार, उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी को सत्ता छोड़ने पड़ी थी। तब, राहुल गांधी के अनुसार, प्र.मंत्री मोदी ने कहा, हमें यह मालूम है और तब तुम सत्ता में आओगे।
- राहुल गांधी का सीडब्ल्युसी की बैठक में यह किस्सा सुनाने का मकसद शायद कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को विश्वास दिलाना था कि कांग्रेस सत्ता में आएगी और यह प्र.मंत्री मोदी भी मान रहे हैं।

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 29 सितम्बर। आक्रामक और पूर्ण आत्मविश्वास से भरे राहुल गांधी ने सीडब्ल्युसी से कहा कि चीफ इलैक्शन कमिश्नर (सीईसी) ज्ञानेश कुमार को हटाना "आर-पार की लड़ाई है।"

उन्होंने कहा कि कुमार पद से हटेंगे और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ही उनका इस्तीफा सुनिश्चित करेंगे, ठीक उसी तरह जैसे धर्मेन्द्र प्रधान के मामले में हुआ था।

राहुल गांधी ने एक किस्सा सुनाया कि जब वे लोकसभा में विपक्ष के नेता बने, तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के साथ एक बैठक में उन्होंने कुछ नामों का विरोध किया था और उन लोगों से पूछा था कि जब वे इन नामों का विरोध कर रहे हैं, तो इन लोगों की नियुक्ति कैसे आगे बढ़ा सकते हैं।

राहुल के अनुसार, मोदी ने इसका जवाब उसी अंदाज में दिया, जिस तरह इंदिरा गांधी दिया करती थीं।

तब राहुल ने कहा कि इंदिरा गांधी को सत्ता छोड़नी पड़ी थी।

तब प्रधानमंत्री ने कहा कि हाँ, हमें यह पता है और जब हम जाएंगे तो आप सत्ता में आएंगे।

इसके बाद, राहुल ने हंसते हुए सीडब्ल्युसी के सदस्यों से कहा कि "प्रधानमंत्री भी मानते हैं कि हम सत्ता में आएंगे, लेकिन कांग्रेस के लोगों को ही विश्वास नहीं है कि हम सत्ता में आएंगे।" उन्होंने कहा कि पिछले दो वर्षों से जब वे तथ्यों और जानकारी के

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

पाकिस्तान के कारण बाँग्लादेश का परमाणु ऊर्जा संयंत्र अटका

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 29 सितम्बर। ऐसे समय में, जब बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों को फिर से मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, उसे एक अलग वास्तविकता का सामना करना पड़ा है। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए परमाणु ईंधन लेकर जा रही एक रूसी उड़ान को अपने हवाई क्षेत्र से गुजरने की अनुमति नहीं दी। बांग्लादेश के पहले

- परमाणु ईंधन लेकर आ रही रूसी उड़ान को पाकिस्तान ने अपने हवाई क्षेत्र से नहीं गुजरने दिया।

परमाणु ऊर्जा संयंत्र की यूनिट-2 के लिए परमाणु ईंधन की पहली खेप 24 सितंबर को पहुंचने वाली थी।

इसका समय महत्वपूर्ण है, क्योंकि बांग्लादेश अपने पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र में जल्द से जल्द व्यावसायिक उत्पादन शुरू करना चाहता है। देश इस समय कई दशकों के सबसे गंभीर ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है। ऐसे में पाकिस्तान द्वारा हवाई क्षेत्र की अनुमति

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अगले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करेगा

याचिका में चीफ इलैक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने इस तरह से काम किया, जैसे, वे चुनाव आयोग की ओर से कोई भी निर्णय ले सकते हैं

- जबकि, याचिका के अनुसार, तीन सदस्यीय चुनाव आयोग में सर्वसम्मति से निर्णय लेने का प्रावधान है और अगर तीनों चुनाव आयुक्तों में सर्वसम्मति नहीं बन रही है तो बहुमत से निर्णय होना चाहिए।

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 29 सितम्बर। सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ दायर याचिका पर अगले हफ्ते सुनवाई करने पर सहमत हो गया। याचिका में आरोप लगाया गया है कि उन्होंने चुनाव आयोग के अन्य दो चुनाव आयुक्तों- सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी की मंजूरी के बिना, अकेले ही भारतीय निर्वाचन आयोग के नाम पर फैसले लिए।

वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के सामने इस याचिका का उल्लेख किया।

सिंह ने कहा, बहु-सदस्यीय आयोग बनाने का उद्देश्य यही था और कानून भी यही कहता है कि फैसला सर्वसम्मति से या बहुमत के आधार पर होना चाहिए। लेकिन जिस तरह चुनाव आयोग ने काम किया है, उससे इस बात पर गंभीर संदेह पैदा होता है कि विशेष गहन पुनरीक्षण (स्पेशल इन्टेन्सिव रिवीजन/एसआईआर) की पूरी प्रक्रिया के लिए वास्तव में चुनाव आयोग का कोई फैसला था भी या नहीं। क्योंकि अगर आयोग ने सर्वसम्मति से फैसला नहीं लिया है, तो --- कोर्ट ने जो फैसला लिया है, वह भी इस आधार पर लिया है कि यह आयोग का फैसला है। इसलिए यह एक गंभीर मुद्दा है।"

सीजेआई ने निर्देश दिया, "इसे अगले सप्ताह की सूची में शामिल करें।"

याचिका में " को वारंटो" रिट जारी करने की मांग की गई है। इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त से यह बताने को कहा गया है कि उन्होंने किस अधिकार के तहत ऐसा काम किया और कर रहे हैं, मानो वो अकेले ही उस सामूहिक निर्णय लेने की शक्ति का इस्तेमाल करने के हकदार हों, जो संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत, एक संस्था के तौर पर चुनाव आयोग को सौंपी गई है।

'मैं किसी भी सूरत में भाजपा के नेतृत्व से नहीं जुड़ूँगा'

शरद पवार का वक्तव्य काफी असाधारण माना जा रहा है

- पवार के बारे में यह कहा जाता है कि अपने छः दशक के राजनीतिक जीवन में वे अपनी प्रतिस्पर्धी पार्टियों व नेताओं को सदा उलझाए रखते हैं, अपनी वक्तव्यबाजी से तथा अंतिम क्षणों में ऐसा निर्णय लेते हैं, जिससे बाकी पार्टियाँ व नेता सदा अचंभित रहते हैं।

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 29 सितम्बर। एनसीपी (एसपी) के प्रमुख शरद पवार, जो "अटकलों का खेल" खेलने के लिए जाने जाते हैं, ने अब एनसीपी के दोनों गुटों के विलय या भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए की ओर जाने की संभावना से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। मुंबई में एक पार्टी बैठक को संबोधित करते हुए वरिष्ठ नेता ने कहा, "हम कहीं नहीं जा रहे हैं। हम किसी के साथ नहीं जाएंगे। अगर आप आना चाहते हैं, तो हमारे साथ आइए।" उन्होंने यह भी कहा कि उनकी पार्टी महाराष्ट्र में महा विकास अघाड़ी और राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन का हिस्सा रहते हुए, खुद को स्वतंत्र रूप से मजबूत करेगी।

यह बयान कई महीनों से चल रही अटकलों के बाद आया है। पवार की एनसीपी (एसपी) और विरोधी एनसीपी गुट के बीच दोबारा एकता की संभावना को लेकर चर्चा तेज हो गई थी। यह दूसरा गुट अब सुनेत्रा पवार के नेतृत्व में है, क्योंकि अजित पवार का निधन हो चुका है। इस चर्चा को उस समय और बल मिला, जब पवार ने इस साल की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ मीटिंग की। इसके अलावा, दोनों पक्षों के नेताओं और केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीच भी बातचीत हुई थी। मीडिया में ऐसी बातें चल रही थीं कि दोनों गुट फिर से एक हो सकते हैं और उसके बाद उनके एनडीए के साथ जाने की संभावना बन सकती है। इसलिए पवार ने अब बिल्कुल साफ कर दिया है कि उनका ऐसा कोई विचार नहीं है और उन्होंने पार्टी संगठन को मजबूत करने तथा सूखे से राहत जैसे मुद्दों पर ध्यान देने की बात कही है।

यह पवार के छह दशक लंबे राजनीतिक करियर में खेले गए "अटकलों के खेल" के पुराने पैटर्न के अनुरुप है। वे रणनीतिक अस्पष्टता, सोच समझकर चुनी गई चुप्पी और अचानक राजनीतिक गठबंधन बदलने /बनाने के लिए जाने जाते हैं, जैसे 1999 में कांग्रेस से अलग होकर एनसीपी बनाना या महाराष्ट्र में गठबंधन के समीकरणों को संभालना। उन्होंने बार-बार अपने सहयोगियों और विरोधियों, दोनों को

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

ज्ञानेश के बचाव में भाजपा ने 12 मुख्यमंत्रियों को उतारा

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 29 सितम्बर। भारतीय जनता पार्टी ने अपने 12 मुख्यमंत्रियों को उनके अपने राज्यों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए मैदान में उतारा। इसका

- भाजपा ने इंडिया गठबंधन पर बिना आधार के चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाने का आरोप लगाया।

उद्देश्य चुनाव आयोग के भीतर मतभेद की खबरों के बीच मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के आरोपों का जवाब देना था। यह कदम कांग्रेस द्वारा ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग को लेकर सोमवार से देशभर में जिला स्तर पर विरोध प्रदर्शन शुरू करने की योजना से एक दिन पहले उठाया गया।

भाजपा की ओर से जारी एक बयान के अनुसार, मुख्यमंत्रियों ने राहुल गांधी

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सुप्रीम कोर्ट ने लगाई आरसीए का चुनाव परिणाम जारी करने पर रोक

हाईकोर्ट ने दौसा सचिव बृजकिशोर के खिलाफ स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किया

- सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिये हैं कि राजस्थान हाईकोर्ट मामले में लंबित याचिका का मैरिट के आधार पर निर्धारित तिथि पर फैसला करे।

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर, 29 सितंबर। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव कराने की छूट देते हुए, चुनाव का परिणाम जारी करने पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही, अदालत ने राजस्थान हाईकोर्ट को कहा है कि वह मामले में लंबित याचिका का मेरिट के आधार पर निर्धारित तिथि पर फैसला करे। सीजे सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की खंडपीठ ने ये आदेश मेघा गौड़ व अन्य की ओर से दायर विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने याचिकाकर्ता को कहा है कि वे याचिका में उठाए गए व्यापक मुद्दों को लेकर बीसीसीआई बनाम बिहार क्रिकेट एसोसिएशन की याचिका की कार्रवाई में शामिल हो सकते हैं। दूसरी ओर, राजस्थान हाईकोर्ट ने दौसा जिला क्रिकेट संघ की याचिका पर सुनवाई करते हुए आरसीए के चुनाव परिणाम को याचिका के अंतिम फैसले के अधीन रखा है। इस याचिका में प्रदीप नागर को सचिव के तौर पर वोट डालने का अधिकार देने सहित अन्य गुहार की गई हैं।

सुनवाई कोर्ट में याचिकाकर्ताओं ने 29 सितंबर को निर्धारित आरसीए चुनाव की प्रक्रिया को लेकर कई आपत्तियां उठाईं। याचिकाकर्ता की ओर से आरसीए में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को लेकर भी सवाल उठाए गये। इसके साथ ही कहा गया कि चुनाव, खेल अधिनियम व आरसीए के संविधान के अनुरूप सख्ती से किए जाने चाहिए। इसके अलावा, कुछ नवगठित जिला क्रिकेट संघों के मतदान अधिकार, पात्र पदाधिकारियों की सूची में सुधार, वैधानिक पर्यवेक्षक की नियुक्ति, नौ सदस्यीय एपेक्स काउंसिल का गठन, लोकपाल की नियुक्ति, सदस्य जिला क्रिकेट संघों से संबंधित लंबित विवादों का निस्तारण संबंधित मुद्दे भी उठाए गए। वहीं अतिरिक्त महाधिवक्ता शिव मंगल शर्मा ने बताया कि आरसीए के चुनाव मंगलवार को ही आयोजित किए जा रहे हैं और परिणाम भी शाम तक ही घोषित किए जाना निर्धारित है। जिस पर कोर्ट ने चुनाव परिणाम जारी करने पर रोक लगा दी है।

वहीं दौसा क्रिकेट एसोसिएशन और उसके पूर्व सचिव प्रदीप नागर की ओर से दायर याचिका कि एसोसिएशन के वर्तमान सचिव बृजकिशोर उपाध्याय को आरसीए चुनाव में भाग नहीं लेने दिया जाए, पर सुनवाई करते हुये, अदालत ने स्पष्ट आदेश जारी किया कि बृजकिशोर उपाध्याय को चुनाव के दिन भाग लेने से नहीं रोका जाए। अदालत ने इसके साथ प्रदीप नागर द्वारा स्थगन के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि ये 29 सितंबर 2026 को होने वाले चुनाव के परिणाम इस याचिका के फैसले के अधीन रहेंगे। स्थगन प्रार्थना पत्र के मामले में सुनवाई करते हुए कहा गया कि रिट याचिका की गुणावगुणों के निस्तारण पर विपरीत प्रभाव नहीं डाले। इस मामले में बृजकिशोर उपाध्याय की ओर से अधिवक्ता एस.एस. होरा पैरवी के लिये पेश हुये थे। इस मामले में आदेश न्यायाधिपति चन्द्र प्रकाश श्रीमाली ने दिये।

इस मामले में पूर्व सचिव प्रदीप नागर का कहना है कि वर्ष 2024 में गलत तरीके से उन्हें सचिव के पद से हटाया गया था और उन्हें आरसीए के

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'जयपुर का "यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी" का दर्जा बचाने के लिए कार्य योजना दें'

जयपुर, 29 सितंबर। राजस्थान हाईकोर्ट ने पिंक सिटी की वैश्विक पहचान व 'यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी' का दर्जा बचाने के मुद्दे पर गंभीरता जताते हुए राज्य सरकार सहित, अन्य संबंधित विभागों व अफसरों से इसकी

- हाई कोर्ट ने राज्य सरकार व संबंधित विभागों से दो सप्ताह में रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए।

कार्य योजना देने के लिए कहा है। इसके साथ ही, अदालत ने परकोटे में हो रहे अवैध व अनियमित निर्माण, अतिक्रमण और ऐतिहासिक भवनों में बदलाव को लेकर संबंधित अफसरों से जवाब देने के लिए कहा है। जस्टिस प्रमिल कुमार माथुर ने ये आदेश परकोटा संरक्षण से जुड़ी मीडिया

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

ट्रंप एआई पर "रेग्युलेटरी" नियंत्रण को चीन से अमेरिका की औद्योगिक स्पर्धा के चश्मे से ही देख रहे हैं

ट्रंप, इस कारण से एआई की प्रगति व विकास पर कोई अंकुश लगाने के सख्त खिलाफ हैं

- दूसरी ओर एआई इण्डस्ट्री के स्थापित लीडर्स, एआई की निरंकुश दौड़ से इतना भयभीत हैं कि उन्होंने अपने कई नवीनतम "इनोवेशन" व मॉडल, बाज़ार में नहीं बेचने का निर्णय लिया और अरबों खर्च कर के विकसित ये "इनोवेटिव प्रोडक्ट्स" अभी बाज़ार में रिलीज़ नहीं हुए हैं।

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 29 सितंबर। कोविड महामारी के दुनिया भर में फैलने की घटना को याद कीजिए। मध्य चीन के वुहान शहर की एक प्रयोगशाला से एक रोगाणु बाहर निकला और दुनिया भर में लोगों को संक्रमित करने लगा। लाखों लोग संक्रमित हुए और लाखों की मौत हुई, जिससे पूरी दुनिया में अभूतपूर्व स्वास्थ्य संकट पैदा हो गया।

एआई के उन्नत मॉडलों से होने वाले नुकसान की संभावनाओं को लेकर इस समय जो डर व्यक्त किया जा रहा है, वह कुछ-कुछ वैसा ही है। नवीनतम एआई मॉडल्स के बेकाबू असर को देखते हुए "ओपनएआई" के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने अपने नवीनतम एआई मॉडल "जीपीटी6.1एस्ट्रा" को फिलहाल जारी नहीं करने का फैसला किया है।

ओपनएआई ने कुछ साल पहले अपना "चैट जीपीटी" मॉडल जारी करके पूरी दुनिया में सनसनी पैदा कर दी थी। इसकी क्षमताएं बेहद प्रभावशाली थीं। इसके बाद से एआई मॉडल और उत्पादों ने ऐसी बहुमुखी प्रतिभा और क्षमताएं दिखाई हैं, जो पहले केवल प्रयोगों और प्रयोगशालाओं के स्तर पर ही देखने को मिलती थीं। इन क्षमताओं ने उन लोगों को भी चिंतित कर दिया है, जिन्होंने शुरुआत में ये एआई सिस्टम बनाए थे।

अभी जो स्थिति सामने आ रही है और जिसे प्रमुख एआई कंपनियों ने भी नोट किया है, वह यह है कि कुछ एआई प्लेटफॉर्म अपने सीमित लैब एनवायरमैंट से बाहर निकल रहे हैं और बिना किसी इंसानी निगरानी के इंटरनेट पर कंप्यूटर सिस्टम को हैक कर रहे हैं। इस प्रक्रिया में वे खुद-ब-खुद वायरस या रोगाणुओं की तरह अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं और कंप्यूटर सिस्टम पर हमला करने वाली एक सेना की तरह बिना इजाज़त अपनी पहचान बना रहे हैं।

हाल में ऐसी दो घटनाएं सामने आईं। पहली घटना में सॉफ्टवेयर कंपनी "हगिंग फेस" पर हमला किया गया। दूसरी में, ऑस्ट्रेलिया की सरकार के कई नेटवर्क पर बड़े पैमाने पर हमला और हैकिंग हुई। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, ओपन एआई ने साफ किया कि इससे "सर्विसेज़ ऑस्ट्रेलिया", "एनएसडब्ल्यू ब्यूरो ऑफ क्राइम स्टैटिस्टिक्स एण्ड रिसर्च", "विक्टोरियन डिपार्टमैंट ऑफ हैल्थ" और "आस्ट्रेलियन इन्स्टिट्यूट ऑफ हैल्थ एण्ड वैलफेयर", सभी प्रभावित हुए।

इन घटनाओं के बाद पूरे पश्चिमी मीडिया जगत में एआई को लेकर चिंता बढ़ गई है और अब मीडिया नए एआई मॉडलों के बुरे असर और उनसे जनता को नुकसान पहुँचने की संभावनाओं पर लगातार रिपार्ट कर रहा है।

इस घटनाक्रम को देखते हुए नये एआई मॉल्डस बनाने वाली प्रमुख कंपनियों में से एक, ओपनएआई ने अपने नए उत्पाद की रिलीज़ को रोक दिया है। मंगलवार को बाज़ार में अपने नवीनतम एआई उत्पाद को कमर्शियल तौर पर लॉन्च करने के बजाय, कंपनी अब इस बात पर ध्यान दे रही है कि ये एआई एजेंट प्रयोगशाला के नियंत्रित वातावरण से बाहर कैसे निकल सकते हैं।

एआई मॉडलों की इन अनियंत्रित और स्वतंत्र क्षमताओं को देखने के बाद, उद्योग के वरिष्ठ नेता, एआई शोधकर्ता, मॉडल बनाने वाले विशेषज्ञ और अन्य लोग मांग कर रहे हैं कि एआई मॉडलों का विकास कुछ समय के लिए धीमा किया जाए। उनका कहना है कि ऐसे एआई मॉडलों को आगे विकसित करने से पहले उनमें सुरक्षा उपाय लगाए जाने चाहिए, ताकि उनका अनियंत्रित व्यवहार रोका जा सके।

शीर्ष एआई कंपनियों के सीईओ और वरिष्ठ विशेषज्ञ मंगलवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप से मिल रहे हैं। बैठक में एआई के विकास और एआई इंडस्ट्री के लिए संभावित नियमों पर चर्चा होगी। ट्रंप ने एआई मॉडल के इनोवेशन और विकास की गति को रोकने के विचारों का लगातार विरोध किया है, खासकर तब, जब चीन अपनी एआई इंडस्ट्री को बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहा है।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

मुख्यमंत्री ने 30 कृषि उपज मंडियों में विकास कार्य स्वीकृत किए

जयपुर, 29 सितंबर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य की विभिन्न कृषि उपज मण्डी समितियों के आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ बनाने के लिए 57 करोड़ 41 लाख रुपये की लागत के विभिन्न विकास कार्यों के प्रस्ताव को

- इन कार्यों से किसानों व व्यापारियों के लिए आधारभूत सुविधाओं का विस्तार होगा।

स्वीकृति प्रदान की है। इससे मण्डी यार्ड निर्माण, विद्युत कार्य, संपर्क सड़कों का निर्माण तथा क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के कार्य करवाए जाएंगे। मुख्यमंत्री द्वारा प्रदान की गई इस स्वीकृति से कृषि उपज मण्डी समिति बज्जू (बीकानेर), नोखा (बीकानेर), खाजूवाला (बीकानेर), श्रीडूंगरगढ़

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)